

प्रेषक,

डी०पी० गैरोला,  
प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी,  
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महाधिवक्ता,  
मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर,  
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग:1

देहरादून : दिनांक ०५ मई, 2012

**विषय :** मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में राज्य की ओर से पैरवी/बहस हेतु अधिवक्ता आबद्ध किया जाना ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम राज्यपाल सम्यक विचारोपरान्त मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के समक्ष राज्य की ओर से पैरवी/बहस किये जाने हेतु निम्नलिखित अधिवक्ताओं को उनके नाम के सम्मुख अंकित पद पर एक वर्ष के लिए आबद्ध करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	अधिवक्तागण का नाम	पदनाम
01	श्री तनवीर आलम खान	उप महाधिवक्ता(सिविल)
02	श्री बी०डी० काण्डपाल	उप महाधिवक्ता(सिविल)
03	श्री डी०के० शर्मा	उप महाधिवक्ता(किमिनल)
04	श्री आर०पी० नौटियाल	सहायक महाधिवक्ता(किमिनल)
05	श्री अमित भट्ट	सहायक महाधिवक्ता(किमिनल)

2- उपर्युक्त आबद्धता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि यह एक व्यवसायिक आबन्धन है, किसी 'सिविल पद' पर नियुक्ति नहीं है। इस आबन्धन को उत्तराखण्ड राज्य द्वारा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के और बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है तथा आबद्ध अधिवक्ता भी इसे कभी भी समाप्त कर सकते हैं। आबद्ध अधिवक्ता अपनी आबद्धता के दौरान उत्तराखण्ड राज्य के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार के मामले में किसी अन्य व्यक्ति/संस्था की आबद्धता स्वीकार नहीं करेंगे न ही राज्य के विरुद्ध कोई विधिक परामर्श देंगे। आबद्ध अधिवक्ता विधि परामर्शी निदेशिका के उपबन्धों का कड़ाई से पालन करेंगे।

क्रमशः.....2



- 3- अधिवक्ताओं को अनुमन्य फीस की दरों के आदेश पृथक से जारी किये जा रहे हैं।
- 4- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
- 5- कृपया उक्त अधिवक्तागण को तदनुसार सूचित करने तथा आबन्धन हेतु उनकी सहमति प्राप्त कर उन्हें तदनुसार कार्य करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
- 6- सम्बन्धित अधिवक्ता इस आशय का प्रमाण पत्र भी महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड के माध्यम से शासन को प्रस्तुत करेंगे कि उन्हें इन शर्तों पर कोई आपत्ति नहीं है।

भवदीय,

(डी०पी० गैरोला)  
प्रमुख सचिव

संख्या- 117 /XXXVI(1)/2012 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मा० मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव/सचिव/निजी सचिव।
- 2- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के स्टाफ आफीसर/निजी सचिव।
- 3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
- 4- महानिबन्धक, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
- 5- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
- 7- मुख्य स्थायी अधिवक्ता/शासकीय अधिवक्ता, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
- 8- सम्बन्धित अधिवक्तागण, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।
- 9- गार्ड फाईल/एन०आई०सी०।

आज्ञा से,



(धर्मेन्द्र सिंह अधिकारी)  
संयुक्त सचिव